परिवर्तन हो रहा था। वह वर्ष 2018 में पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक यहां से नरकटियागंज से सिकटा होते हुए जयनगर, दरभंगा, रक्सौल के लिए जो गाड़ियां चलती थीं, उनको नहीं चलाया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण, मेरे जन्म स्थल की जगह है और पूर्व में 2014 से 2019 तक मैं वहां से सांसद भी रहा हूं। वह नेपाल से सटा हुआ इलाका है और सुदूर ग्रामीण इलाका पड़ता है। वहां से लोगों को आने-जाने के लिए प्राइवेट बस, जीप और टैक्सी के सिवाय दूसरा कोई संसाधन नहीं है। वहां पर भाड़े में काफी इजाफा हो गया है, प्राइवेट गाड़ी वाले लोग काफी ज्यादा भाड़ा वसूल करते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि सात जोड़ी ट्रेन्स जो पूर्व में चलती थीं, उनको पुनः चलाया जाए। अगर तत्काल चलाने में असुविधा हो रही है, तो एक मेमू ट्रेन नरकटियागंज से चलाई जाए, जो रक्सौल वाया सिकटा कम से कम दिन में तीन, चार, पांच बार अप एंड डाउन करे, जिससे तत्काल लोगों को सहायता मिल सके। महोदय, जन-मानस के काम के लिए ही सरकार होती है और रेलवे उसका बहुत बड़ा संसाधन होता है।

वहां पर आवागमन बाधित है, पब्लिक काफी परेशान है। वहां पर रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हो गया है, बड़ी लाइन भी बन गई है, लेकिन अभी तक ट्रेन्स चालू नहीं हुई हैं, जिससे आम जनमानस में सरकार के प्रति उदासीनता है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वहां पर कम से कम मेमू ट्रेन जल्दी से जल्दी चलाई जाए और पूर्व में जो सात जोड़ी ट्रेन्स चलाई जाती थीं, उनको चलाया जाए।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्री अनिल बलूनी जी।

Issue of development of Lansdowne in Uttarakhand

श्री अनिल बलूनी (उत्तराखंड)**:** उपसभापति जी, मैं उत्तराखंड के लोकप्रिय हिल स्टेशन लैंसडाउन के विषय को यहां पर रखना चाहता हूं। महोदय, अगर दिल्ली से ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश)**:** सर, एलओपी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र)**:** सर, एलओपी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः नहीं, माननीय सदस्यगण, यह ज़ीरो ऑवर है। ज़ीरो ऑवर में आप जो कुछ भी बोलेंगे, वह नहीं जाएगा। जो वक्ता हैं, केवल उनकी ही बात जाएगी। प्लीज़, आप बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंहः *

श्री संजय राउतः *

* Not recorded

श्री उपसभापतिः आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। Please take your seat. आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। बलूनी जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनिल बलूनीः महोदय, अगर दिल्ली एनसीआर के इलाके में किसी से भी पूछा जाए कि दिल्ली के सबसे नजदीक हिल स्टेशन कौन सा है, तो वह मसूरी या नैनीताल का नाम लेगा। ...(**व्यवधान**)... महोदय, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। दिल्ली के सबसे नजदीक हिल स्टेशन लैंसडाउन है। जो कि दिल्ली से केवल 270 किलोमीटर की दूरी पर है। महोदय, यह नैसर्गिक छटा से परिपूर्ण है। हिमालय का पूरा दृश्य वहां से दिखता है। ...(**व्यवधान**)... वहां पर जो बेस कैम्प है, ...(**व्यवधान**)... ऋषि कण्व आश्रम भी वहां पर है, वहां पर सिद्धबली की बहुत बड़ी पीठ है, वहां पर तारकेश्वर महादेव भी हैं। महोदय, वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड होने का कारण लैंसडाउन के विकास में कुछ बाधाएं आ रही हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी के आग्रह है कि अगर लैंसडाउन के कुछ हिस्से को डिनोटिफाई कर दिया जाए या कैंटोनमेंट बोर्ड के नियम में कुछ छूट दी जाए, तो निश्चित रूप से लैंसडाउन देश का लोकप्रिय और पर्यटकों का पसंदीदा टूरिस्ट स्थल बन सकता है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्रीमती सुलता देव। ...(**व्यवधान**)... यह ज़ीरो ऑवर है और ज़ीरो ऑवर में जिनके नाम सैंक्शंड हैं, वे ही बोलेंगे, और अन्य किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

Need for tackling underfunding and red-tapism in the implementation of schemes under the Nirbhaya Fund

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा)**:** सर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर अपना मत दे रही हूं, जो कि निर्भया फंड के संबंध में है। महोदय, निर्भया फंड के अंतर्गत आने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं कम फंडिंग और लालफीताशाही की समस्या से ग्रसित हैं, जिन पर न केवल ओडिशा में बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ...(**व्यवधान**)... निर्भया फंड के तहत धन का कम उपयोग हुआ है। यह फंड केवल तीन परियोजनाओं और 7 राज्यों में केंद्रित हो गया है। जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। One Stop Centre के संबंध में धन का प्रभाव असंगत होता जा रहा है। इसके प्रभावी कार्यान्यवन में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मैं तो यह बोलती हूं कि जो फंड दिया जा रहा है ...(**व्यवधान**)... जैसे ये तीन परियाजनाओं और 7 स्टेट्स को कैरी कर रहा है, तो इसमें सारे देश के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को लाना चाहिए।

अगर देखा जाए तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में 11,273 केसेज़ पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है। इसके साथ ही पैसे की कमी हो रही हैं, कम फंडिंग हो रही है, युटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। 'वन स्टॉप सैंटर' में जो कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए भी सैलरी का प्रावधान नहीं हो पा रहा है, स्टाफ की शॉर्टेज है,